

अस्थायी अध्यापकों को नियमित करने पर सरकार जल्द लेगी निर्णय, महाधिवक्ता ने कोर्ट को दी जानकारी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता ने स्वीकार किया कि सात अगस्त 1993 से दिसंबर 2000 के बीच नियुक्त अस्थायी अध्यापकों को नियमित करने पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। वहीं, वर्ष 2000 के बाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के संजय सिंह केस में दिए गए फैसले के तहत फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सरकार को सही जानकारी नहीं दी। दो मुद्दों को मिक्स कर भ्रमित कर उलझा रखा है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश की प्रति मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश च्यायर्मूट रोहित रंजन अग्रवाल ने विनोद कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर दिया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सहायता प्राप्त कॉलेजों में सहायक शिक्षकों और व्याख्याताओं के नियमितीकरण के मामले में दाखिल याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा, शिवेंदु ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने पक्ष रखा। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट के आदेश के पालन के लिए कुछ समय मांगा। कहा कि आदेश की जानकारी सरकार को देंगे। उम्मीद है सरकार 1993 से 2000 तक नियुक्त एक हजार से अधिक अध्यापकों को नियमित किया जाएगा। वर्ष 2000 के बाद नियुक्त अध्यापकों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर अध्यापकों को वेतन देने व सेवा जारी रखने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद सरकार भुगतान रोक रखा है। कोर्ट ने कहा 7 अगस्त 1993 से दिसंबर 2000 तक नियुक्त अध्यापकों का नियमितीकरण धारा 33 जी के तहत होना चाहिए।

**शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा
कैलेंडर, कमेटी गठित, असिस्टेंट प्रोफेसर
का रिजल्ट जल्द होगा जारी**

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी) जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेगा। आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने कमेटी गठित कर दी है। बृहस्पतिवार को पदभार संभालते ही उन्होंने अफसरों एवं सदस्यों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक के दौरान उनका पूरा फोकस काम जल्द शुरू करने पर था। उन्होंने कमेटी को निर्देश दिए कि भर्ती परीक्षाओं के प्रस्तावित कैलेंडर पर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा विज्ञापन संख्या-50 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों का रिजल्ट शीघ्र जारी करने के लिए भी कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट मांगी है। साथ ही अध्यक्ष ने टीजीटी कला एवं जीव विज्ञान के लंबित रिजल्ट को लेकर भी कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट तलब की है। वहाँ, विज्ञापन संख्या-42 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बीच में रोके गए इंटरव्यू को लेकर भी कमेटी गठित की है। पहले सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी। अध्यक्ष जानना चाहती है कि हाईकोर्ट का स्टै हटने के बाद बीच में रोके गए इंटरव्यू को शुरू करने में कोई तकनीकी पेच तो नहीं है। अध्यक्ष ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करते हुए अधियाचन मांगने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। यह जिम्मेदारी उन्होंने उप सचिव शिवजी मालवीय को सौंपी है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व में कार्यवाहक अध्यक्ष की ओर से सेवा शर्तों, पटल अनुभाग, प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली और वेबसाइट को लेकर गठित की गई कमेटियों की रिपोर्ट को अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव मनोज कुमार समेत सभी 12 सदस्य एवं अन्य अफसर मौजूद रहे।

प्रयागराज में बाइक समेत बांध में समाया युवकरूभाई बोला- आंखों के सामने बह गया, बचा नहीं पाएँ जांच में जुटी पुलिस्से जा। प्रयागराज को सेवा में देती मर्लेशिया बांध में आ

मजा। प्रयागराज के मजा में दवरा गुलारया बाध में आज दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में झारखण्ड के एक युवक की मौत हो गई। पवन तिरकी (22) नामक युवक बाइक चलाते समय बांध के पानी में डब गया और घटना के चार घंटे बाद उसका

A close-up photograph of a young man with dark hair and a mustache, looking slightly to his right.

का, लाकन झूँब गया। पुलिस न भाक पर पहुँचकर युपक का तलाश शुरू की। घटना के चार घंटे बाद शव और बाइक को पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया। मृतक पवन के पिता मनोहर तिरकी कोरांव थाना क्षेत्र के कपूरी गांव के सदासहाय विद्यालय में नौकरी करते हैं और परिवार के साथ रहते हैं। पवन अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसकी मौत से परिवार को गहरा आघात लगा है। पवन की मां अंजना रोते-रोते बेसुध हो गई। छोटी बहन सृष्टि और साक्षी का रो-रोकर बुरा हाल था। झारखण्ड से चर्चेरा भाई अनीश कुछ दिन पहले कोरांव घूमने आया है और उसकी आंखों के सामने पवन ढूँब गया। वह बेबस होकर देखता रह गया, इतना कहने के बाद वह बिलख पड़ा। इंस्पेक्टर मांडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदिव्यन ने समन्वा दर्ज कर जारी भारक कर दी है।

महिला एडवोकेट हत्याकांड पर वकीलों में आक्रोशः यूपी बार काउंसिल बोला- जैसे बंगाल में महिला डॉक्टर की हत्या हई, वैसा ही हआ



हाईकोर्ट सख्त : कहा - सरकार को गुमराह कर रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी, सीएम ले संज्ञान



है, जिन्हें नवंबर 2023 में बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद तमाम अदालती आवेदनों के बावजूद उनके समायोजन को लेकर कई परिपत्र जारी किए गए। उन परिपत्र के आलोक में 1993 से 2000 के बीच नियुक्त शिक्षकों को 2000 के बाद नियुक्त शिक्षकों के समान समायोजन की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ 2000 से पहले

नियुक्त हुए शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिकारी आरके ओझा ने दलील दी कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को संबोधित परिपत्र आठ जुलाई 2024 को जारी परिपत्र का हवाला दिया। कहा कि वे शिक्षक जिनकी सहायता प्राप्त संस्थान में सेवाएं

**अर्द्धसैनिक बलों में सिपाही के 39,481 पदों पर भर्ती
के लिए आवेदन शुरू, 14 अक्टूबर है आखिरी तिथि**



प्रयागराज। अर्द्ध सैनिक लों में सिपाही के 39,481 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की वेबसाइट पर भर्ती का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। 18 से 23 वर्ष तक के वर्गीस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन परीक्षा जनवरी और फरवरी में कराई जा सकती है। सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) सिपाही भर्ती परीक्षा— 2024 के अंतर्गत बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी में चयन होगा। पिछले वर्ष सिपाही के 46,617 पदों के लिए भर्ती आई थी। उसके सापेक्ष इस बार कर्ता समय लाइव फाटा अपनी कर्ती होगी। इस पद के फायदे उन्हीं का आवेदन मान्य होगा, एक जनवरी 2025 से प्राप्त हाईस्कूल उत्तीर्ण कर चुके होने वाले आवेदन के समय ही केंद्र विकल्प देना होगा। इसमें पुरुष अध्यर्थी की लंबाई 170 और महिलाओं की लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आवेदन में कोई गत घटना पर पांच से सात नवंबर तक संशोधन का मौका दिया जाएगा।

**गर्लफ्रेंड को छोटे कपड़ों में देख फूटा गुस्सा, गला दबाकर
की जमकर पिटाई, पुलिस बोली अभी नहीं आ सकते**

प्रयागराज। नना एग्रीकल्चर हॉलेज में बंगाल की एक छात्रा नो मां के सामने गला दबाकर उसका रहमी से पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्रा को स्पोर्ट्स के कपड़े में खेलकर आरोपी दोस्त भड़क गया और उसने मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान छात्रा बेहाश हो गई। आरोप है कि बीच चाव करने आई मां से भी मारपीट की गई। मामले में छात्रा की मां ने आरोपी दोस्त के खिलाफ नैनी थाने में तहरीर दी है। जानकारी के अनुसार, बंगाल की रहने वाली छात्रा नीनी स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज में बीबीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह कॉलेज के ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। उसका पूरा परवार बगाल में रहता है। छात्रा की मां ने बताया कि शाहगंज क्षेत्र का रहने वाला आरोपी यथार्थ सोनकर उनकी बेटी के कॉलेज में पढ़ाई करता है। उनकी बेटी और यथार्थ दोनों दोस्त थे। 29 अगस्त को उनकी बेटी कैंपस के अंदर स्पोर्ट्स के कपड़े में वालीबॉल खेल रही थी। बेटी को छोटे कपड़ों में देखकर आरोपी यथार्थ भड़क गया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस बात की सूचना उन्हें मिली तो वह बंगाल से सोमवार को प्रयागराज पहुंची। उसके बाद मंगलवार को बेटी के साथ यथार्थ के घर पर शिकायत लेकर गई तो वहां पर भी उनकी बेटी से उसने मारपीट की। उसके बाद उसने शाहगंज थान पहुंचकर मामले की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मामले में समझौता करा दिया। मां का आरोप है कि तीन सितंबर शाम करीब 5रु30 बजे यथार्थ सोनकर उनके बेटी को फोन कर मिलने के लिए कहा, लेकिन उसने मिलने से इन्कार कर दिया। इस पर यथार्थ ने फोन पर धमकी देते हुए कहा कि तुम्हें जहां जाना हो चली जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाओगी। बुधवार को सुबह जब उनकी बेटी कॉलेज के कंप्यूटर लैब में पहुंची तो वहां पर यथार्थ पहले से मौजूद था, जहां उसने फिर से मारपीट की। उनकी बेटी ने उन्हें फोन कर मामले की जानकारी दी तो वह हॉस्टल

थीम आधारित लाइटें और 84 प्रवेश द्वार कराएंगे महाकुंभ की भव्यता का एहसास, 20 करोड़ रुपये होंगे खर्च

प्रयागराज। महाकुंभ मेले में अलग-अलग अखाड़ों के साथ-सांतों के दर्शन, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन इसे अद्भुत बना देते हैं। शहर में थीम आधिकारित लाइट्टों के अलावा खास वाकार वाले प्रवेश द्वार और स्टंड मनद्वालुओं का स्वागत करेंगे। साथ में उन्हें महाकुंभ की दिव्यता का मनभव कराएंगे। इसके लिए सड़कों के अलावा अन्य प्रमुख स्थलों पर कुल 84 थीमेटिक द्वार बनाए जाएंगे, जिस पर 20.33 करोड रुपये खर्च होंगे। कुंभ मेलाई कारी विजय किरन आनंद के अनुसार, पूरे शहर तथा आसपास के क्षेत्र को कुंभमय करने की योजना को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। इस क्रम में शहर को जोड़ने वाले चारों मार्गों पर भव्य गेट बनाने एवं उन्हें सजाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से वाराणसी, लखनऊ एवं मिर्जापुर रोड पर गेट बने हुए हैं। इसी क्रम में कानपुर मार्ग पर कैलाश द्वार बनाने का निर्णय लिया गया है। इन प्रवेश द्वारों को विशेष तरीके से सजाया जाएगा। इसके तहत ऊंची तीर-धनुष, संगम में स्नान करते साथ शंख समेत

देनांक नौ नवंबर 2023 के शासनादेश से समाप्त की गई है, उन्हें हाईस्कूल के लिए 25,000—रुपये और हाइटरसीडिएट के लिए 30,000—रुपये के मासिक मानदेय पर बनुन्: नियोजित किया जा सकता है। जबकि, यह परिपत्र उन नियुक्तियों पर बाध्यकारी होगा जो 2000 के बाद की गई हैं। लेकिन, उन लोगों के लिए नहीं जो सात अगस्त, 1993 और देसंबर, 2000 के बीच नियुक्त हुए हैं। क्योंकि, वे नियमितीकरण के लिए धारा 33—जी के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह वरिष्ठ अधिकारकों का अशोक खरे ने कोर्ट का यान वेतन भुगतान न होने पर आकर्षित किया। कहा कि कोर्ट ने चार जनवरी 2024 को पारित अंतरिम आदेश में सरकार को उन शिक्षकों की बहाली जारी रखते हुए वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया था। जिनका वेतन आठ नवंबर 2023 से रोक दिया गया है। इसके खिलाफ सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। फिर भी सरकार वेतन भुगतान नहीं कर रही। अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। बताया कि बाहर किए गए शिक्षकों के नियमितीकरण और समायोजन पर सरकार जल्द फैसला लेगी। मौजूदा मामले दो प्रकार के हैं, एक वर्ष 2000 से पहले नियमितीकरण से संबंधित है, जिसे धारा 33—बी, सी, एफ, जी के प्रावधानों के तहत निपटाया जाना है। वहीं, जहां तक वर्ष 2000 के बाद की नियुक्तियों का सवाल है, उसे संजय सिंह (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार निपटाया जाना है। इसके द्वारा 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय के साथ 11 माह के लिए समायोजित किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने परिपत्र भी जारी किया है। वेतन भुगतान का मामला भी विचाराधीन है। दोनों पक्षों के तर्क से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक तथ्य राज्य सरकार के संज्ञान में सही ढंग से नहीं लाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी जानबूझ कर दो मुद्दों को मिला रहे हैं। पहला, सात अगस्त 1993 से दिसंबर 2000 के बीच की गई नियुक्तियां, जिन्हें धारा 33—जी के अनुसार नियमित किया जाना आवश्यक है। जबकि दूसरा, 2000 के बाद की गई नियुक्तियां, जो संजय सिंह (सुप्रा) के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत आती हैं। अधिकारियों की ओर से जारी किए जा रहे परिपत्र विधायी मंशा और धारा 33—जी के प्रावधानों के विपरीत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारी जानबूझकर दो मुद्दों को मिला रहे हैं और इसे जटिल बना रहे हैं।

400 करोड़ की ठगी के मामले में 450 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, अभिषेक समेत छह बनाए गए आरोपी

प्रयागराज। प्रॉपटी-शेयर में निवेश के नाम पर 400 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को निहारिका वैचर्स के एमडी अभिषेक द्विवेदी समेत छह आरोपियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। करीब 450 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने सभी को आरोपी बनाया है। बीते छह जून को शिवकुटी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक द्विवेदी, उसके पिता डॉ. ओम प्रकाश,

सास निरुपमा, ड्राइवर शैलेंद्र, मददगार टीकम चंद्र जायसवाल, पार्टनर नरेन्द्र सिंह नेगी को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में पता चला था कि आरोपी अभिषेक ने पार्टनर के साथ मिलकर अयोध्या, नोएडा समेत अन्य जगहों पर करोड़ों रुपये की जमीन की डील की थी। वहीं, पूछताछ में आरोपी अभिषेक ने अपने ऊपर लगे ठगी के आरोप को बेबुनियाद बताया था। मामले में पुलिस ने अब उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट बनाकर दाखिल कर दी है। अब जल्द ही कोर्ट में केस का ट्रायल चलेगा। निवेशकों ने पुलिस को बताया था कि इस ठगी में आरोपी अभिषेक की पत्नी निहारिका भी शामिल है। पुलिस ने निहारिका को दबोचने के लिए गोविंदपुर रिस्थित घर से लेकर अयोध्या तक दबिश दी लेकिन पुलिस अबतक निहारिका को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को निहारिका की लोकेशन पता चल गई है। बताया गया कि उसपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस को दी तहरीर में कौशल ने बताया था कि सिविल लाइंस में निहारिका वेंचर्स नाम की कंपनी है। यह कंपनी रियल एस्टेट और शेयर बाजार में लोगों का पैसा निवेश करती है। लालच दिया जाता है कि हर महीने पांच से छह फीसदी मुनाफा दिया जाएगा। इसी लालच में फंसकर करीब 70 से 80 लोगों ने लाखों रुपये निवेश किए थे। मालिकों का कहना था कि चुनाव के कारण पैसे देने में देरी हो रही है। चुनाव खत्म होते ही सभी के पैसे लौटा दिए जाएंगे। लेकिन, इस बीच पता चला कि कंपनी ने अपना ऑफिस बंद कर दिया।

एसटीएफ ने प्रयागराज से पकड़ा, पुलिस भर्ती परीक्षा का लीक पेपर रीवां के रिसोर्ट में पढ़ाया था

प्रयागराज। यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराने वाले दो शातिरों को अरेस्ट किया है। पकड़े गए जालसाजों ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा— 2023 और उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा— 2023 का प्रश्नपत्र लीक कराया था। इनके गैंग के अन्य सदस्य जेल जा चुके हैं। आरोपी संजय सिंह कुशवाहा और कामेष्वर नाथ मौर्या फरार चल रहे थे। शुक्रवार को एसटीएफ ने प्रयागराज के कीड़गंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों काली स्कार्पियों से भाग रहे थे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के बाद अभ्यर्थियों को रीवां के रिसोर्ट ले जाया गया था। वहीं सभी अभ्यर्थियों से रुपये लिए गए और उन्हें पेपर पढ़वाया गया। रिसोर्ट मालिक को इसके लिए 5 लाख रुपये दिए गए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी/ सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा—2023 11-02-2024 को कराई गई थी। इसी इसके बाद उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा— 2023 की परीक्षा आयोजित हुई थी। उत्तर प्रदेश प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायत मिलने पर सरकार ने परीक्षाओं को निरस्त करते हुए प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी थी। एसटीएफ के उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह, निरीक्षक जय प्रकाश राय जांच में जटे थे।

सम्पादकीय.....

जल्दीबाजी का कानून

हाल ही में कोलकाता में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ दुराचार और हत्या की घटना ने पूरे देश को उद्देलित किया है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल व देश के अन्य भागों में चिकित्सा विरादरी के लोग व छात्र-छात्राएं आंदोलनरत रहे हैं। निश्चित ही यह दुर्भाग्यपूर्ण व दुखद घटना थी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जिस तरह की राजनीति होती रही है, वह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। विडब्बना है कि एक अमानवीय घटना को राजनीतिक अस्त्र बनाने और उसका प्रतिकार करने का माध्यम बना दिया गया। इसी कड़ी में आनन-फानन में बुलाए गए पश्चिम बंगाल विधानसभा के सत्र में जल्दीबाजी में बलात्कार विरोधी विधेयक 'अपराजिता' पारित कर दिया गया। यदि किसी महिला के साथ बलात्कार के बाद मृत्यु हो जाती है या उसे छोड़ भी दिया जाता है, तो विधेयक बलात्कारी के लिये मृत्युदंड का प्रावधान करता है। कहा जा रहा है कि दुराचार के बाद युवा डॉक्टर की निर्मम हत्या के बाद पश्चिम बंगाल में जो आक्रोश आम लोगों में उपजा है उसको दबाने की यह एक राजनीतिक निहितार्थ वाली प्रतिक्रिया है। दरअसल, यह विधेयक जनता के व्यापक विरोध के बाद सामने आया है। जनता ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से न्याय और जवाबदेही की मांग करती रही है। वहीं राज्य सरकार का दावा है कि विधेयक का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शासन की प्रतिबद्धता के प्रति आश्वस्त करना है। हालांकि, ममता सरकार द्वारा आनन-फानन में लाए गए विधेयक ने इस बात को लेकर बहस छेड़ दी है कि यह कदम राज्यव्यापी असंतोष को शांत करने के लिये महज राजनीति से प्रेरित प्रतिक्रिया है। दरअसल, राज्य में ज्ञानान्वयन कंसेप्ट के तेजा तन्त्र के अपरि विजेता का ज्ञानान्वयन

टृणमूल कांग्रेस के नता जनता के नारा परावध का सामना कर रहे हैं। हाल ही में आंदोलनकारी प्रशिक्षु डॉक्टरों पर भीड़ के हमले और प्रदर्शन के दौरान पुलिस के दमन से लोगों में भारी गुस्सा है। यही नहीं, टीएमसी के कई नेताओं की असंवेदनशील टिप्पणियों ने भी आंदोलनकारियों के आक्रोश को और बढ़ाया है। दरअसल, राज्य के लोगों खासकर महिलाओं में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि जिस राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री हो, वहां एक युवा महिला डॉक्टर के साथ दुराचार व हत्या के मामले में राज्य सरकार ने ईमानदार प्रतिक्रिया नहीं दी। टीएमसी के कई नेताओं द्वारा की गई अनर्गल बयानबाजी ने भी आग में धी डालने का काम किया। दरअसल, राज्य सरकार ने इस कांड में किरकिरी होते देख मामले को दबाने का प्रयास किया। पीड़िता के परिवार ने भी उनके साथ किये गए व्यवहार को लेकर तीखा प्रतिवाद किया था। फिर प्राथमिकी दर्ज करने में देरी व मेडिकल कालेज के परिसर में आंदोलनरत छात्रों पर एक भीड़ के हमले ने यह संदेश दिया कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। इस तरह के कृत्यों से राज्य में घटना का विरोध और तेज होता चला गया। निस्संदेह, इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा जमकर राजनीति की गई, लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार व प्रशासन ने मामले में प्रतिक्रिया दी, उसने लोगों के गुस्से को बढ़ाया ही है। एक पहलू यह भी है कि नया विधेयक केंद्र की भारतीय न्याय संहिता के साथ तालमेल नहीं रखता, जो बलात्कार के लिये मृत्युदंड का प्रावधान नहीं करती। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के इसी तरह के विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिये जूझते रहे हैं। दरअसल, विगत के अनुभव बताते हैं कि मौत की सजा इस तरह के अपराधों पर नियन्त्रण करने में सफल नहीं हुई है। कानून के विशेषज्ञ ऐसी तुरत-फुरत सजा को मानव अधिकारों की प्रकृति के विरुद्ध बताते रहे हैं। तभी विधेयक के पारित होने को टीएमसी सरकार की हताशा से उपजा कदम बताया जा रहा है। आने वाले वक्त बताएगा कि यह विधेयक कानून बनने के बाद जमीनी हकीकत में बदलाव लाएगा या फिर कानूनों की लंबी सूची में इजाफा ही करेगा। हालांकि, इस विधेयक को अभी राज्यपाल व राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार करना है, फिर इसकी प्रभावकारिता और नैतिक निहितार्थों से जुड़े व्यापक प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं। बेहतर होगा कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करके तेज व निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करे।

एजेंसी

90 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस 32 सीटों पर और नेशनल काफ़रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पांच सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। 18 व 25 सितम्बर तथा 1 अक्टूबर को यहां (तीन चरण) चुनाव होने जा रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में राहुल का बड़ा वादा

जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल काफ्रेंस गठबन्धन ने प्रचार अभियान की शुरुआत बड़े बादे को दोहराते हुए कर दी है। राहुल गांधी ने बुधवार को कश्मीर के रामबन में एक विशाल रैली को सम्बोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 1947 में कांग्रेस की सरकार ने जम्मू-कश्मीर के राजा को हटाकर उसे राज्य का दर्जा दिया था लेकिन भाजपा सरकार ने पांच वर्ष पहले राज्य के दर्जे को समाप्त कर यहां एक राजा (लेफ्टीनेंट गवर्नर) को बैठा दिया है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि अब तक केन्द्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया जाता रहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी को अवसर मिला तो जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटायेगी। 90 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस 32 सीटों पर और नेशनल काफ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पांच सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। 118 व 25 सितम्बर तथा 1 अक्टूबर यहां (तीन चरण) चुनाव जा रहे हैं। उल्लेखनीय है इस संवेदनशील राज्य में वर्षों के बाद चुनाव होने जा है। 5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर लिये लागू अनुच्छेद- 370 हटा कर इसे और लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बना था। उसी साल विधानसभा चुनाव होना था लेकिन वह आधार पर टाल दिये गये यहां चुनाव कराने की अनिच्छा भाजपा की केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश अंतर्गत चुनाव कराना लायी हो गया है। महबूबा मुपती पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) गठबन्धन का हित तो नहीं है लेकिन समझा जा है कि जरूरी हुआ तो उस समर्थन कांग्रेस-एनसी को सकता है। अनुमान लगाये रहे हैं कि भाजपा से लोगों ने इस कदर नाराजगी है कि कश्मीर में बड़ी मुश्किलों सामना करना पड़ सका कांग्रेस से अलग हो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आंदोलन पार्टी बनाने वाले गुलाम आजाद की भी राह कोई आनंदी मार्गी जा रही है। उ

अब तक 10 ही सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है माना जा रहा था कि उसके भाजपा से गठबन्धन हो सकता है लेकिन अब लगता है कि वह भाजपा की बी टीम के रूप लड़ेगी। वैसे पहले ही उसके चार प्रत्याशियों ने मैदान छोड़ दिया है। उधर दूसरी तरफ भाजपा अपनी रणनीति बनाए में मशगूल है लेकिन ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिन्हें लेकर उसे जनता के बीच जाना मुश्किल हो जायेगा। पहली बात तो यही कि अनुच्छेद- 370 हटाये जाने को लेकर वहां की जनता कापूर नाराज है। उस प्रक्रिया के दौरान न तो वहां की जनता की राली गयी थी, न ही उसके बावें वादे पूरे हुए जिनका उल्लेख कर कहा जाता रहा। फिर जम्मू-कश्मीर के लोगों खुशहाली आयेगी। जहां तक आतंकवादी घटनाओं से मुक्ति दिलाने की बात कही गयी थी तो वैसा कुछ भी हासिल न नहीं हो सका। घाटी में अब भी पांच समर्थित आतंकी गुटों के हमले गाहे-बगाहे होते रहते हैं। इनमें वालों की संख्या अच्छी-खासी है। कश्मीरी पंडितों की वापसी भी एक प्रमुख मुद्दा था जिसके बारे में भाजपा

काफी दावे करती रही है। उस मोर्चे पर भी सरकार के हाथ खाली हैं। बहुत कम संख्या में कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई भी तो वे वहां स्थायी नहीं बसाये जा सके हैं। बाहरी मजदूरों की हत्याएं भी हुई हैं, कश्मीरी पंडित अब भी वहां कोई महफूज महसूस नहीं करते। जिस प्रकार से कश्मीरियों के बारे में भाजपा समर्थित लोगों ने अपमानजनक टिप्पणियां की हैं और जैसे लम्बे समय तक घाटी के लोगों की इंटरनेट सुविधा छीनी गयी थी, उन सारी मुश्किलात का जवाब लेने का अवसर जम्मू-कश्मीर के लोगों को अब मिल गया है। राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर में बेहद लोकप्रिय हुए हैं। याद हो कि 7 सितम्बर, 2022 को कन्याकुमारी से निकली राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी, 2023 को श्रीनगर में ही हुआ था जिसे पूरे देश की तरह ही जबर्दस्त प्रतिसाद मिला था। फारख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आदि न केवल समापन रैली में शामिल हुए थे, बल्कि वे इंडिया गठबन्धन के भी हिस्सेदार हैं जो कई अवसरों पर हुई बैठकों एवं रैलियों में बराबर शिरकत करते रहे हैं।

आईसी 814: सवालों को दबाने की कोशिश

सर्वमित्रा सुरजन

आईसी 814 उस विमान का नाम है, जिसे 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आते वक्त अगवा कर लिया गया था। पत्रकार श्रीजॉय चौधरी और आईसी-814 के कैप्टन देवी शरण की लिखी किताब श्पलाइट इन टू फियररु द कैप्टन स्टोरीश पर अनुभव सिन्हा ने आईसी 814 नाम से ही सीरीज बनाई है। इस सीरीज में वास्तविक घटनाओं को ही दिखाया गया है। काठमांडू से भारतीय एजेंट द्वारा दी गई चेतावनी की अनदेखी से लेकर विमान के हाईजैक होने और सात दिन बाद अफगानिस्तान के कंधार में तीन दुर्दात आतंकादियों मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख, और मुश्ताक अहमद जरगर की रिहाई तक की सारी घटनाओं को इस सीरीज में पेश किया गया है। काठमांडू से निकला जहाज ईंधन न होने के कारण अमृतसर में उतारा गया, फिर लाहौर और दुबई होते हुए आखिर में कंधार पहुंचा और इन सात दिनों तक जहाज में सवार आम यात्रियों की जिंदगी पूरी तरह से अपहरणकर्ताओं की दया पर ही रही। एक यात्री की मौत के अलावा बाकी सारे यात्रियों को विमान के चालकदल समेत आखिर में छुड़ा लिया गया, लेकिन इसकी भारी कीमत देश ने चुकाई है। क्योंकि जिन तीन आतंकादियों को कांग्रेस के शासनकाल में पकड़ा गया था,

उन्हें भाजपा की अटलबिहारी वाजपेयी सरकार ने छोड़ा और उसके बाद देश की संसद पर हमले समेत कई और आतंकी घटनाएं हुईं। यह सब किसी उपन्यास का प्लॉट या फिल्म की कहानी होती, तो पहले ही दिन आठ-दस कमांडो जांबाजी दिखाते और सब चंगा सी हो जाता। जितने देर विमान बंधक रहता, उतनी देर प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में सारे दल-बल के साथ गहन चिंतन में ढूबे नजर आते, उनके सलाहकार और अधिकारी देशप्रेम को ऊपर रखते हुए किसी प्रोटोकॉल की परवाह नहीं करते और सैन्य जवानों की काबिलियत पर भरोसा करते हुए उन्हें खुली छूट दे दी जाती कि जैसे भी हो, चाहे भारत की जमीन पर या विदेशी जमीन पर अपहर्ताओं को मार गिराओ और बंधकों को छुड़ा दो। लेकिन अफसोस कि हकीकत इससे काफी अलग रही। हकीकत यह थी कि विमान अमृतसर में जब थोड़ी देर रुका, तब भी भारतीय कमांडो कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, यही सबसे बड़ा सवाल है। इस सीरीज में इसी सवाल से एक बेचौनी उपजती है, जो सीधे दर्शकों तक पहुंचती है। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लौहपुरुष कहे जाने वाले गृहमंत्री लालकृष्ण आडवानी, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल इन सब की भूमिकाओं और प्राथमिकताओं पर सवाल उठते हैं। सीरीज में जिस तरह नौकरशाही को जनता सरोकारों से बिल्कुल कटा हुआ दिखाया गया है, वह रवैया कहीं न कहीं बेचौन करता यह रवैया सही नहीं है, लेकिन सच के काफी करीब है। अनुसन्धान ने एक वरिष्ठ अधिकारी के किरदार से टू मच डेमोक्रेटों का संवाद भी कहलवाया है, आज के दौर की भाजपा का लेकिन भाजपा के पश्चात शासनकाल में भी शायद देश की हकीकत थी। आइए 814 सीरीज ने वाजपेयी शासनकाल की एक बाकामी को जनता को दिला दिया है। शाइनिंग इंसिपियर जैसे नारों के जरिए तो भाजपा की कोशिश यही रही कि कार्रवाई से लेकर कंधार हाईजैक संसद पर हमले जैसी तात्पुरी घटनाओं को जनता बुरे खबरों की तरह भूल जाए, लेकिन 2014 के चुनाव परिणामों ने बता दिया कि जनता ने इन घटनाओं का याद रखा। हालांकि 2014 के फिर से भाजपा आई और से अब तक फिर वही कोशिश शुरू हो गई है। पुलवामा घटना को 2019 के चुनाव तक नरेन्द्र मोदी ने बखूबी इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अभी आइए 814 सीरीज को देखकर तात्पुरी कि इतने बरसों में कुछ भी नहीं बदला है। तब भी घटनाएँ फौरन बाद प्रधानमंत्री से बदलने की कोशिश होती रहती है। इतना बड़ा संकट आने के बाद भी देश के मुखिया से संपर्क हो पाना, विडंबना है। या वह

और, ये सोचना होगा। लेकिन 14 फरवरी 2019 को भी तो ऐसा ही हुआ था। पुलवामा दोपहर 3 बजकर 10 मिनट पर सैनिकों को ले जा रही बस विस्फोटक भरी गाड़ी टकराता है औरउस वक्त प्रधानमंत्री जिंदगी कार्बोट के जंगलों में मैन वर्सेल वाइल्ड की शूटिंग में व्यस्त थे। शाम सात बजे वे वहाँ से बाहर निकले। इस बीच 5 बजकर 10 मिनट पर रुद्रपुर में भाजपा के कार्यक्रम को उन्होंने फोटो से संबोधित किया। उस भाषण में उन्होंने पुलवामा हमले कोई उल्लेख नहीं किया। तब क्या श्री मोदी को पुलवामा हमले की जानकारी नहीं थी, या उन्होंने इस बारे में इसलिए नहीं बोता क्योंकि उन्हें डर था कि कानून विपक्ष इसे मुद्दा न बना ले विनाशक इतना बड़ा हमला होने वाला बाजूद प्रधानमंत्री डिस्कवरी के साथ समय बिता रहे थे। पुलवामा की घटना को पांच साल से ऊपर हो गए हैं, इस बीच कई और गंभीर सवारियाँ इस हमले को लेकर उठायी गई हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर सब दबा दिए गए। भाजपा तो अब तीसरी बार सत्ता में आ गयी है, लेकिन अतीत के कुछ सवारियाँ अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ सकती। रहे हैं और इसलिए उन सवारियाँ से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आईरेस 814 में अपहृताओं के नामों भोला और शंकर जैसे नाम का शामिल किए गए, इसे लेकर नेटफिलिक्स को ही धेर लिया

गया। अब नेटपिलक्स ने स्पष्ट कर दिया है कि अपहृताओं के असली नाम भी दिखाए जाएंगे। लेकिन इस हाईजैक की एक भुक्तभोगी ने भी बताया है कि दो अपहृताओं को भोला और शंकर के नाम से बुलाया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि सीरीज में विमान के भीतर का जो कुछ दिखाया गया है, उस वक्त सब वैसा ही घटा था, इसमें कोई अतिरेक नहीं बरता गया है। लेकिन फिर भी भाजपा समर्थकों और भक्त पत्रकारों द्वारा अनुभव सिन्हा को निशाने पर लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक भायावह घटना को हिंदू-मुसलमान बनाकर पेश करने की कोशिश शुरू हो गई है। अनुभव सिन्हा में स्वघोषित राष्ट्रवादियों, राष्ट्रप्रेमियों, भारत मां के सपूत्रों, हिंदुत्व के रक्षकों को देश का दुश्मन, हिंदुत्व का शत्रु, वामपंथी नजर आ रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी अनुभव सिन्हा की फिल्में विवादों में आ चुकी हैं। अनुभव सिन्हा की आर्टिकल 15, भीड़, मुल्क और थप्पड़ जैसी फिल्में तो ऐसी हैं, जिनसे कई लोगों की दुखती रग पर हाथ पड़ जाता है। सोशल मीडिया के प्रचार तंत्र के जरिए भाजपा को देश की सबसे महान पार्टी, नरेन्द्र मोदी को अवतारित नायक और भाजपा के शासन को असली आजादी का जो मिथ गढ़ा गया है, वो सब ऐसी फिल्मों से भरभारकर गिरने लगता है। अनुभव सिन्हा की तमाम फिल्मों की खासियत यही है कि वे दर्शकों पर कोई विचार थोपते नहीं हैं, बल्कि उसे मंथन करने पर मजबूर कर देते हैं। जबकि मौजूदा शासक यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता विचार-विमर्श से दूर रहे, किसी भी मुद्दे पर अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल न करे, केवल वही देखे और समझे, जो समाचार चौनलों के जरिए उसे समझाया जा रहा है। चौनल भी दर्शकों के दिमाग पर कब्जा करने में पूरी मेहनत कर रहे हैं। हाल ही में उप्र में आदमखोर भेड़िये को पकड़ने की खबर एक रिपोर्टर ने खुद को जाल में फँसा कर की, इससे पहले युद्ध या बाढ़ जैसी आपात खबरों को स्टूडियो में इसी तरह माहौल बनाकर परोसा जा चुका है। दरअसल इस वक्त मीडिया घराने जिन पूँजीपतियों की पूँजी से संचालित हो रहे हैं, उनके हित साधना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए पूँजीपति, सरकार, मीडिया इन सबके गठजोड़ से देश चल रहा है। इस व्यवस्था में कोई रचना अगर खलल पैदा करती है, दर्शकों को सवाल करने पर मजबूर करती है, भाजपा के शासन की नाकामी को सामने लाती है, तो जाहिर है उस रचना को देशविरोधी साबित करने की कोशिश की जाएगी। आईसी 814 के साथ इस समय यही कोशिश चल रही है। देखना होगा कि जनता इसमें किस तरह अपने विवेक का इस्तेमाल करती है।

राजनीति में झूठ बन रहा लोकतंग के अस्तित्व का खतरा

नन्दू बनर्जी

लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें अक्सर सोचती हैं कि उनके मतदाता मूर्ख हैं। उनके पास ऐसी धारणा बनाने के अच्छे कारण हो सकते हैं क्योंकि उनमें से बहुत से लोग अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और चारित्रिक विशेषताओं के मामले में वहाँ रहने के लायक नहीं हैं। उनमें से कई पर तो जग्न्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। मतदाताओं के पास उम्मीदवारों के चयन में बहुत कम विकल्प होते हैं। वे मतदान केंद्रों पर ऐसे उम्मीदवारों को बोट देने जाते हैं, जो राजनीतिक रूप से झूठे या जोड़-तोड़ करने वाले हो सकते हैं। उम्मीदवारों को अक्सर उनके मतदाता झूठे वायदों पर मोहित होकर या बिक कर चुनते हैं। कल्पना करें कि अगर राजनीति में झूठ बोलना प्रतिबंधित कर दिया जाये तो सरकार में बैठे उन आदतन झूठ बोलने वालों का क्या होगा जो अर्थव्यवस्था और प्रशासन की झूठी छवि बनाने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी करते हैं। लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार, ग्रेट ब्रिटेन के हिस्से वेल्श की नवनिर्वाचित लेबर सरकार ने राजनीति में झूठ बोलने को अवैध बनाने का संकल्प लिया है। वेल्श सरकार ने कहा कि 2026 में अगले सेनेड (वेल्श संसद) चुनावों से पहले श्विश्व स्तर पर अग्रणीश कानून बनाया जायेगा। सेनेड के सदस्यों ने इसे लोकतंत्र में झूठ बोलने से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरे से निपटने के अपने प्रयास में एक रेतिहासिक क्षण बताया। वेल्श सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून एक स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जानबूझ कर धोखा देने के दोषी पाये गये सदस्यों और उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करेगा। राजनेताओं

द्वारा झूठ बोलने को गैरकानूनी घोषित करने के आव्वान का नेतृत्व कर रहे एक प्रमुख वेल्श राजनेता एडम रॉबर्ट प्राइस ने कहा था, जो घोषणा की गई है वह वास्तव में ऐतिहासिक है, विश्व स्तर पर अग्रणी है। हमारी सरकार की ओर से हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारा लोकतंत्र राजनेताओं द्वारा धोखे पर सामान्य प्रतिबंध 1 लगाने वाला दुनिया का पहला लोकतंत्र होगा। हम एक वैशिक आंदोलन की शुरुआत में हैं। हम राजनीतिक झूठ को गैरकानूनी घोषित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसत्य लोकतंत्र के दिल में है, लेकिन राजनेताओं में विश्वास खत्म हो गया है। यह एक अस्तित्वगत खतरा है। उन्होंने कहा, अगर मतदाता निर्वाचित लोगों की बातों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो लोकतंत्र टूटने लगता है। इ हालांकि, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड सहित दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रस्तावित वेल्श कानून के प्रभाव की भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी, जो ग्रेट ब्रिटेन के दो अन्य घटक हैं, लेकिन यह कुछ लोकतांत्रिक देशों में आंदोलन को जन्म दे सकता है। वेल्श एक बहुत छोटा देश है, जो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। 2021 तक, वेल्श की आबादी 3,107,494 थी और इसका कुल क्षेत्रफल 21,218 वर्ग किलोमीटर था। इसलिए, वेल्श में जो कानूनी रूप से संभव हो सकता है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जैसे बड़े लोकतंत्रों में उम्मीद करना असंभव हो सकता है, जहां झूठ बोलना पार्टी की राजनीति का एक अभिन्न अंग है, जो राजनेताओं की आपराधिक प्रवृत्ति को उजागर करता है और बेहद कम अभियोजन और सजा दर दर्ज करता है। झूठ

बोलने वाले राजनेता की पहचान की जा सकती है और उपकड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसे राजनेताओं द्वारा चलाई जाने वाली झूठ बोलने वाली सरकार के बारे में क्या, जो अक्सर झूठ बोलते हैं और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं? भारत में स्थिति की कल्पना करें, जहां राजनीतिक शासक अपने राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जननया मतदाताओं को गुमराह करने के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से अक्सर महत्वपूर्ण संख्याओं में हेराफे करवाते हैं। यह बढ़ती महंगाई या घटते रोजगार या संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के समय में झूठी खुशी को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। ऐसे सरकारी कार्यों के बारे में क्या जो राष्ट्र की कीमत पर केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों या समूहों व लाभ पहुंचाते हैं? ऐसे कार्यों के पीछे व्यक्तियों की पहचान कैसी जाये? सरकार अपने सार्वजनिक संचार इरादे के अनुरूप संबंधित टोकरियों को बड़ा या छोटा करके आधिकारिक सूचकांक में हेराफेरी कर सकती है। उदाहरण के लिए, ऐसे समय में जो खाद्य पदार्थों, सब्जियों, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, संचार और यात्रा लागत, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यय और उसकी कीमत आसमान छू रही हैं, भारत में थोक और खुदरा मूल्य सूचकांक दोनों में बड़ी गिरावट बताई जा रही है। कोई उन्हें उठोकरियों के आकार पर दोष दे सकता है जिनमें उन दैनिक आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। इस तरह के सरकारी धोखे से कैसे निपटें? लोकतांत्रिक समाज में सरकारी धोखे पर कई बार बहस हुई है, जिससे लोकतांत्रिक दुनिया भर

सार्वजनिक क्षेत्र में झूठ का प्रसार हुआ है। लोग एक चुनी हुई सरकार पर भरोसा करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग अपनी चुनी हुई सरकार के भ्रामक कार्यों और बयानों पर भी भरोसा कर लेते हैं। वास्तव में, सरकार के झूठ लोकतांत्रिक व्यवस्था के कामकाज के लिए किसी एक राजनेता के सार्वजनिक झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सरकार के झूठ का असर विधायिका और न्यायपालिका पर भी पड़ता है। धोखा एक संक्रामक बीमारी की तरह फैलता है और विधायिका और न्यायपालिका सहित लोकतंत्र के अन्य स्तरभौं को भी अपनी चपेट में ले लेता है। सरकारी झूठ को नियन्त्रित करना सबसे मुश्किल होता है। जब कोई सरकार झूठ बोलती है, तो वह सत्ता में बैठे राजनेताओं से लेकर भरोसेमंद नौकरशाहों और कर्मचारियों तक पूरी शासन प्रणाली में फैल जाती है। लगभग पूरी लोकतांत्रिक दुनिया में न्यायपालिका स्पष्ट रूप से इस अवधारणा को खारिज करती है कि संवैधानिक कानून को सरकार की झूठ बोलने की क्षमता को सीमित करने के लिए कुछ करना चाहिए। मुख्यिर संरक्षण कानून, सूचना का अधिकार कानून और नौकरशाही व्यवहार में राजनीतिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने वाले मानदंड जैसे तंत्र भले ही अच्छे इरादे वाले हों, लेकिन वे शायद ही ऐसी व्यवस्था में काम करें जो सरकार और उसके चुने हुए राजनीतिक आकाओं को लाभ पहुंचाने के लिए झूठ को बढ़ावा देने पर आमादा हो। 2022 में, इस विषय पर अमेरिका स्थित कॉलंबिया विश्वविद्यालय के नाइट फर्स्ट अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा किये गये विचार-विमर्श ने कुछ प्रासंगिक प्रश्न उठाये थे।



हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी की बायोग्राफी सामने आया है। जिसमें सपना के एक स्टेज डांसर से अब फिल्मी पर्दे पर दर्शकों के लिए बन रही है। बुधवार को इस मूरी का लेटेस्ट टीजर रिलीज कर दिया गया है। जिसमें सपना के स्टेज डांसर से सुपरस्टार बनने तक के संघर्ष से भरपूर सफर को दिखाया गया है। चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़ी कुछ बातें सेलेक्ट की बायोपिक की लिस्ट में अब हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी का नाम शामिल हो गया है। 4 सितंबर को सपना के जीवन पर बनने वाली फिल्म 'मैडम सपना' का एलान मेकर्स की तरफ से कर दिया गया है। इस मूरी का डायरेक्शन महेश भट्ट कर रहे हैं। वहीं, मूरी की अनाउंसमेंट के साथ ही इसका लेटेस्ट टीजर वीडियो भी

सामने आया है। जिसमें सपना के एक स्टेज डांसर से सफलता के मुकाम तक पहुंचने का संघर्ष दिखाया गया है। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी पर जल्द ही फिल्म बनने वाली है। हाल ही में बुधवार को इस मूरी का लेटेस्ट टीजर रिलीज कर दिया गया है। जिसमें सपना चौधरी के अलग-अलग वीडियो विलप्स शामिल किए गए हैं। ये टीजर एक डॉक्यूमेंट्री की तरह लग रहा है, जो उनके जीवन के अलग-अलग पहलुओं को दर्शता है। सपना ने इस टीजर को शेयर करते हुए लिखा कि ये बायोपिक सिर्फ एक फिल्म नहीं हैं, बल्कि उनके संघर्ष, सपनों और उन कठिन रास्तों की कहानी है जिन्हें उन्होंने पार किया है। उन्होंने अपने फैस से

कश्मीर में अल्फा के शेड्यूल के बाद घर वापस आई बॉलीवुड दिवा शर्वरी



कश्मीर में अपनी आमामी फिल्म अल्फा की शूटिंग कर रही बॉलीवुड दिवा शर्वरी अब अपने घर वापस लौट आई हैं। बुधवार को इंस्टाग्राम स्टोरीज पर 2.2 मिलियन फॉलोअर्स वाली शर्वरी ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने घर की झलक दिखाई। उन्होंने पोस्ट के कैश्यून में लिखा, घर आकर अच्छा लगा जासूसी जगत की पहली महिला प्रधान फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट हैं। फिल्म में आलिया और शर्वरी दोनों ही सुपर-एंजेट की भूमिका में हैं और ऐसा लग रहा है कि आदित्य चोपड़ा उन्हें जासूसी जगत की पैक की अल्फा गर्ल्स के रूप में पेश कर रहे हैं। शिव रखैल के निर्देशन में बनी अल्फा का निर्माण आदित्य चोपड़ा कर रहे हैं। शर्वरी प्यार का पंचानामा 2, बाजीराव मस्तानी और इशोनू के टीटू की स्टीटी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुकी हैं। उन्होंने यशराज फिल्म्स के बैनर तले निर्माता आदित्य चोपड़ा की कहानी

पर आधारित वरुण वी शर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित क्राइम कॉमेडी श्वर्टी और बबली 2 से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। यह फिल्म 2005 की फिल्म बटी और बबली का सीक्वल है। इस फिल्म में सेफ अली खान, रानी मुखर्जी और सिद्धांत चतुर्वेदी ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित हॉरर कॉमेडी मुंज्या में बेला की भूमिका निभाई। इसमें अभय वर्मा, सत्यराज और मोना सिंह थे। मैडॉक फिल्म्स के तहत अमर कौशिक और दिनेश विजन द्वारा निर्मित, यह मैडॉक

सपना चौधरी की बायोपिक 'मैडम सपना' की टीजर रिलीज, पर्दे पर दिखेगा डांसर का संघर्ष

“

सपना ने फैस से कहा है कि जैसे ही उनकी कहानी स्क्रीन पर आएगी, उन्हें और ज्यादा प्यार और प्रोत्साहन की जरूरत होगी। 'मैडम सपना' को शाइनिंग सन स्टूडियो के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें महेश भट्ट का निर्देशन और विनय भारद्वाज और रवीना ठाकुर का प्रोडक्शन है।

समर्थन की अपील की है। सपना ने फैस से कहा है कि जैसे ही उनकी कहानी स्क्रीन पर आएगी, उन्हें और ज्यादा प्यार और प्रोत्साहन की जरूरत होगी। 'मैडम सपना' को शाइनिंग सन स्टूडियो के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें महेश भट्ट का निर्देशन और विनय भारद्वाज और रवीना ठाकुर का प्रोडक्शन है। परिणीति चोपड़ा अपने प्रशंसकों को लंदन में बिताए अपने समय की एक सुखद झलक दिखा रही है। अभिनेत्री, जो सोशल मीडिया पर अपने अनुभवों को सक्रिय रूप से साझा करती रही है, ब्रिटेन की राजधानी में अपने समय के हर पल का आनंद ले रही है। इंस्टाग्राम पर अपने हालिया आर्क मी एन्डिंग सेशन के सवालों का जवाब देते हुए, परिणीति ने फिल्म चमकीला में अपनी भूमिका के लिए मिले अपार प्यार के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, एक बात जो मैं निश्चित रूप से कहना चाहती हूं, वह है चमकीला में आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिल्म के बाद हमें इस तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। परिणीति ने यह भी साझा किया कि प्रशंसकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने उन्हें कैसे गहराई से प्रभावित किया है, आप लोगों ने जो कुछ कहा है और कुछ चीजें जो मैंने पढ़ी हैं, गंभीरता से, वे हर दिन मेरे सपनों में आती हैं। अपनी यात्रा पर विचार करते हुए, उन्होंने चमकीला में अमरजोत कौर के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के दौरान आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया और कहा, मुझे इस भूमिका को करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। और मैं अपनी भूमिका को महसूस कर रही हूं। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया है, उसके कारण यह सब इसके लायक था। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद।



परिणीति चोपड़ा जल्द भारत लौटेंगी, एक्ट्रेस ने बताया- लंदन को अपना 'दूसरा घर' और दिल्ली को अपना 'सुसुराल' बताया

परिणीति चोपड़ा अपने प्रशंसकों को लंदन में बिताए अपने समय की एक सुखद झलक दिखा रही है। अभिनेत्री, जो सोशल मीडिया पर अपने अनुभवों को सक्रिय रूप से साझा करती रही है, ब्रिटेन की राजधानी में अपने समय के हर पल का आनंद ले रही है। इंस्टाग्राम पर अपने हालिया आर्क मी एन्डिंग सेशन के सवालों का जवाब देते हुए, परिणीति ने फिल्म चमकीला में अपनी भूमिका के लिए मिले अपार प्यार के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, एक बात जो मैं निश्चित रूप से कहना चाहती हूं, वह है चमकीला में आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिल्म के बाद हमें इस तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। परिणीति ने यह भी साझा किया कि प्रशंसकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने उन्हें कैसे गहराई से प्रभावित किया है, आप लोगों ने जो कुछ कहा है और कुछ चीजें जो मैंने पढ़ी हैं, गंभीरता से, वे हर दिन मेरे सपनों में आती हैं। अपनी यात्रा पर विचार करते हुए, उन्होंने चमकीला में अमरजोत कौर के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के दौरान आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया और कहा, मुझे इस भूमिका को करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। और मैं अपनी भूमिका को महसूस कर रही हूं। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया है, उसके कारण यह सब इसके लायक था। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद।

एक्ट्रेस ने अपनी फिल्मों की पसंदीदा भूमिका को याद किया

अभिनेत्री ने फिल्म हंसी तो फंसी में अपनी पसंदीदा भूमिकाओं में से एक को भी याद किया, उन्होंने साझा किया कि रिक्रूट में एक अनूठा आकर्षण था जो उन्होंने उसके बाद से नहीं देखा। मुझे लगता है कि मेरी पसंदीदा भूमिकाओं में से एक और मुझे लगता है कि आपकी भी हंसी तो फंसी रही है। मुझे नहीं पता, वे अब ऐसी भूमिकाएं नहीं लिखते हैं। उन्होंने टिप्पणी की। यह प्रतिबिंब रचनात्मक कहानी कहने के लिए उनकी प्रशंसा को उजागर करता है जो उनके और उनके दर्शकों के साथ प्रतिध्वनि होता है।

परिणीति ने कहा— अब दिल्ली मेरी सुसुराल है

परिणीति अपना समय लंदन, बॉम्बे और दिल्ली के बीच बांटती रही है। अपने यात्रा कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया, लंदन मेरा दूसरा घर है। बॉम्बे मेरा कार्य शहर है और अब दिल्ली मेरा सुसुराल है। उनके जीवन का यह विभाजन उनके निजी और पेशेवर जीवन दोनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लंदन में परिणीति चोपड़ा का समय काम, अवकाश और आध्यात्मिक कायाकल्प का मिश्रण होता है। 'इशकजादे' अभिनेत्री ने साझा किया कि वह इंग्लैंड की राजधानी छोड़ रही है और जल्द ही घर वापस आ जाएंगी। एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर मिरर सेल्फी की एक सीरीज भी शेयर की, जिसमें उन्होंने स्टाइलिश लैंडर पहनी हुई थी और जैकेट के साथ बाइकर शॉट्स पहने हुए थे। यह एक वॉकिंग आउटफिट है, दोस्तों। और मैं चलते-फिरते आप लोगों से बात कर रही हूं। एक्ट्रेस ने अपनी जीवंत शक्तियत को दिखाते हुए कहा।

बाद उसके होश उड़ जाते हैं। विक्रांत मैसी की 'सेक्टर 36' का ट्रेलर सोशल मीडिया पर मेकर्स ने शेयर किया है। ट्रेलर में विक्रांत और दीपक गैंगस्टर लुक में धमाका करते दिखाई दे रहे हैं। विक्रांत मैसी स्टारर 'सेक्टर 36' शुरुआत से ही चर्चा में रही है। मेलबर्न के मशहूर इंडियन फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने धूम मचाने वाली है। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस क्राइम ड्रामा में विक्रांत और दीपक डोरिया की टॉम एंड जेरी की दौड़ वाकई दिलचस्प लग रही है। 12वीं फेल विक्रांत मैसी एक बार फिर से ओटीटी पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। 'सेक्टर 36' में एक पुलिस अधिकारी झूगी बस्तियों से बच्चों के गायब होने के मामले की जांच करता है। इस दौरान उसका सामना खतरनाक सीरियल किलर से होता है जो बच्चों को क



अंतिम समय में इंसान के मुंह में क्यों डाला जाते हैं तुलसी और गंगाजल ? यहां जानिए कारण

जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद का सफर कैसा होगा इस बात को लेकर दुनिया भर में कई मान्यताएँ हैं। अक्सर देखा जाता है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगाजल और तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। इस परंपरा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति दिलाना है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं।

पवित्रता और शुद्धिकरण

गंगा नदी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गंगाजल व्यक्ति के पापों को धो देता है और उसे शुद्ध करता है। मृत्यु के समय गंगाजल के सेवन से व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। वहीं तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। तुलसी के पत्तों को मृत व्यक्ति के मुंह में डालने का अर्थ है कि उसकी आत्मा को भगवान विष्णु के श्रीचरणों में स्थान प्राप्त हो और उसे मोक्ष मिल सके।

आध्यात्मिक शक्ति

गंगाजल और तुलसी दोनों में आध्यात्मिक शक्तियां मानी जाती हैं। तुलसी के पत्ते और गंगाजल का सेवन व्यक्ति को आधिक शक्ति और भगवान के साथ संपर्क में आने में मदद करता है। गंगाजल और तुलसी के सेवन से व्यक्ति के मन में शांति और भक्ति का भाव जागृत होता है। यह उसे मृत्यु के समय भी भगवान की याद दिलाता है, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है।

धार्मिक मान्यता

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु के समय गंगाजल और तुलसी का सेवन करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसकी आत्मा शर्वग की ओर प्रस्थान करती है। यह परंपरा व्यक्ति के जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी आत्मा को पवित्र और भगवान के समीप पहुंचाने का प्रयास करती है। यह हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रथा है जो मृत्यु के समय भी व्यक्ति को धर्म और अध्यात्म से जुड़े रहने का संदेश देती है।

खाली पेट रोजाना अंजीर खाने सेहत को मिलते हैं जबरदस्त फायदे, आज से शुरू कर दें इसका सेवन



अंजीर को अंग्रेजी में figs कहते हैं। यह एक स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर फल है। इसके सेवन से हमारे शरीर में कई फायदे होते हैं। अंजीर में कई मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा, अंजीर में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैनीशियम, तांबा, आयरन, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन एल जैसे एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो शरीर को हेल्दी रखता है। भिंगोकर अंजीर के सेवन करने से बॉडी को मिलते ये फायदे।

डायबिटीज नियंत्रित रखता

अंजीर का सेवन से डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। रात के समय 3-4 अंजीर भिंगोकर रख दें, इसके बाद रोजाना सुबह इसके सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है।

हीमोग्लोबिन बढ़ाता है

अंजीर एक अमृत फल है इसमें कई सारे पोषक तत्व पाएं जाते हैं। अंजीर में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैनीशियम, तांबा और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व होते हैं। रोजाना खाली पेट भीगे हुए अंजीर खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अंजीर को आप दूध के साथ भी खा सकते हैं।

कैंसर से लड़ता

अंजीर में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स होता है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। प्रतिदिन सुबह भीगे हुए अंजीर के सेवन से खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है।

हड्डियां मजबूत होती

अंजीर में कैल्शियम, पोटेशियम और मैनीशियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है और सूजन को भी कम करता है। भीगे हुए अंजीर खाने से आपकी हड्डियां मजबूत बनेंगी।

पाचन तंत्र बेहतर होता है

अगर आप रोजाना भीगे हुए अंजीर का सेवन करते हैं तो पाचन संबंधित समस्याओं से राहत मिलती है।

क्यों होती है विटामिन डी की कमी, जानिए इसे कैसे कर सकते हैं दूर



धूप में कम समय बिताना

शरीर में विटामिन डी की कमी होना सबसे बड़ा कारण हैं धूप में कम समय बिताना। खासकर सूर्य की अल्ट्रावायलेट बी (प्रूवीबी) किरणें। जब आप धूप में पर्याप्त समय नहीं बिताते हैं, तो आपका शरीर विटामिन डी का निर्माण नहीं कर पाता। आजकल की जीवनशैली में लोग ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं या धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे विटामिन डी की कमी हो सकती है।

खानपान में कमी

विटामिन डी की कमी से लोगों को क्या-क्या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। आज देश की लगभग 80 से 90 प्रतिशत आबादी विटामिन डी की डेफिशियेंसी से जूझ रही है। चलिए जानते हैं, विटामिन-डी की कमी से शरीर में क्या परेशानियां होती हैं और इसकी कमी को कैसे पूरा करना चाहइ।

कैसे जानें कि आप विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं

विटामिन डी की कमी की पहचान करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप समय पर उपचार कर सकें। जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है शरीर कई तरह के संकेत देता है। जैसे थकान और कमजूरी यदि आप दिनभर थकान और ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है।

हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों की कमजूरी भी विटामिन डी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। यदि आप बार-बार बीमार पड़ते हैं या आपकी इम्यूनिटी कमजूर है, तो विटामिन डी की कमी इसके पीछे एक कारण हो सकता है। आपको बता दे कि अगर व्यक्ति को घाव या किसी पररक की छोटी हैं तो उस व्यक्ति का घाव जल्दी नहीं भरता। विटामिन डी की कमी से घाव और छोटे को ठीक होने में समय लग सकता है।

सनस्क्रीन का ज्यादा उपयोग

जिन लोगों की त्वचा अत्यधिक संवेदनशील होती है या जो अक्सर सनस्क्रीन का उपयोग करते हैं उनकी त्वचा पर सूर्य की किरणें ठीक से अवशोषित नहीं होतीं। सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी का उत्पादन कम हो सकता है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल विटामिन डी के प्रभावित कर सकता है। सनस्क्रीन की परत सूर्य की न्तरिकाएँ को रोकती हैं, जिससे त्वचा पर विटामिन डी का उत्पादन घट सकता है।

क्योंकि ज्यादा उपयोग

जिन लोगों की त्वचा अत्यधिक संवेदनशील होती है या जो अक्सर सनस्क्रीन का उपयोग करते हैं उनकी त्वचा पर सूर्य की किरणें ठीक से अवशोषित नहीं होतीं। सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी का उत्पादन कम हो सकता है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल विटामिन डी के प्रभावित कर सकता है। सनस्क्रीन की परत सूर्य की न्तरिकाएँ को रोकती हैं, जिससे त्वचा पर विटामिन डी का उत्पादन घट सकता है।

जैसे

1. फैटेड फिश साल्मन, मैक्रेल, ट्यूना, और सर्दी की मछली।



विटामिन डी की कमी को ठीक करना आवश्यक है, ताकि आप स्वस्थ रह सकें और अपनी जीवनशैली को सुधार सकें। आइए जानते हैं कि विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए कौन-कौन से प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं, ताकि आप इस महत्वपूर्ण पोषक तत्व की कमी को प्रभावी ढंग से अपने डाइट में शामिल कर सकें।

विटामिन डी की कमी को दूर करने के उपाय

ऑफिस में काम करते हैं या घर के अंदर अधिक समय बिताते हैं, तो धूप का समय निकालना आवश्यक है। पोषणयुक्त आहार का सेवन करें, साथ ही अपनी डाइट में विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें।

जैसे

1. फैटेड फिश साल्मन, मैक्रेल, ट्यूना, और सर्दी की मछली।

2. अंडे अंडे की जर्दी में विटामिन डी होता है।

3. डेयरी प्रोडक्ट्स दूध, दही, पनीर।

4. विटामिन डी से फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स जैसे विटामिन डी से युक्त फोर्टिफाइड डाइट में विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोतों से दूर रहते हैं।

5. फोर्टिफाइड संस्पर्धन का रस कई ब्रॉड विटामिन डी से फोर्टिफाइड जूस प्रोवाइड करते हैं।

6. विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर आपकी विटामिन डी की कमी गंभीर है तो डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी सप्लीमेंट्स का सेवन करें। ये आमतौर पर टैबलेट या कैप्सूल के रूप में उपलब्ध होते हैं।

7. सर्दी जीवनशैली अपनाएं

<p

સંક્ષિપ્ત



ગોલ્ડમેન સૈક્સ કી રિપોર્ટ કે બાદ સ્ટૉક મેં આઈ ગિરાવટ, 10 ફીસદી નીચે આપ

સ્ટૉક માર્કેટ મેં ટેલોકોમ કંપની વોડાફોન આઇડિયા કે શેયરોનું મેં કંપની આ ગઈ હૈ। બીએસિં મેં વોડાફોન આઇડિયા કે શેયરોનું મેં ગિરાવટ આઈ હૈ। વોડાફોન આઇડિયા કે શેયરોનું મેં કી 10 ફીસદી કી ગિરાવટ દેખને કો સિલી હૈ। કંપની કે શેયરોનું એક ઘટે કી ટ્રેડિંગ મેં હી વોડાફોન આઇડિયા કે શેયર 10 પ્રતિશત માંથી હૈ। આંકડોની કી માનને તો બ્રોકરેજ ફર્મ ને ટાર્ગેટ પ્રાઇસ કમ હોને કે બાદ શેયરોનું મેં બિકાવાની દેખી હૈ। ઇસે બાદ સુધી 11 બજે હી વોડા આઇડિયા કે શેયરોનું મેં 16.51 પ્રતિશત કી ગિરાવટ આઈ થી। યે 2.29 રૂપયે કાં આકડા રહા। ગિરાવટ કે બાદ વોડા આઇડિયા કે શેયર 16.16 રૂપયે પ્રતિ શેયર કે હિસાબ સે બિક રહે થે।

ઇન્ની કમ હૂઝી કીમત

ગ્રાન્ડબાલ માર્કેટ મેં સબ્સેબ બંડે બ્રોકરેજ ફર્મ ગોલ્ડમેન સૈક્સ કી તરફ સે એક રિપોર્ટ જારી કી ગઈ હૈ જે જિસમે વોડાફોન-આઇડિયા કે શેયરોનું મેં ગિરાવટ આઈ હૈ। ઇસ રિપોર્ટ મેં ફર્મ ને સલાહ દી હૈ કે શેયરોનું કે બેચ દિયા જાએ। ઇસકે બાદ હી શેયરોનું કી કીમત મેં ગિરાવટ આઈ હૈ। શેયર કાં પ્રાઇસ ટાર્ગેટ કો 2.5 રૂપયે પ્રતિ શેયર કર દિયા। ફર્મ કે મુશ્ટાબિક કંપની કો ઇસ સમય મેં ફંડ જુટાને સે અધિક લાભ નહીં હોગા। બાજાર મેં કંપની અપની બઢી હિસ્સેદારી ગંભીર સકતી હૈ। બઢી હિસ્સેદારી ખોને કી સ્થિતિ મેં આગામી તીવને ચાર વર્ષોનું મેં માર્કેટ શેયર મેં તીવની પ્રતિશત કી ગિરાવટ આ સકતી હૈ।

એસી રહી કંપની કી પરફોર્માન્સ

કંપની કે શેયરોનું કી પરફોર્માન્સ અચ્છી નહીં રહી। કંપની બીતે કઈ મહીનોનું સે કાફી સમયાઓનું સે ડિરી હૂઝી હૈ। આંકડોનું પર ગૌર કરેં તો બીતે છે મહીનોનું કે દૌરાન કંપની કે શેયરોનું 5.60 ફીસદી કાં નેગેટિવ રિટર્ન દિયા હૈ। વર્હની પાંચ સિત્મબર 2023 સે અબ તક કંપની મેં નિવેશકોનું કો 24 પ્રતિશત સે અધિક કાર્ટિયન મિલા હૈ।

નૃપાય શુરૂઆતી કારોબાર મેં દો પેસે મજબૂત હોકર 83.95 પ્રતિ ડશ્લલર પર

રૂપાય શુરૂઆતી કારોબાર મેં દો પેસે મજબૂત હોકર 83.95 પ્રતિ ડાલર પર પહુંચ ગયા। વિદેશી મુદ્રા કારોબારિયાનું બતાયા કે અંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર કાં કાં કીમતોનું મેં તેજી, ઘરેલું શેયર બાજારોનું નકારાત્મક રૂઘ ઔર વિદેશી પૂંજીની કી નિકાસી સે સ્થાનીય મુદ્રા કી બઢત સીમિત રહી। અંતર્બેની વિદેશી મુદ્રા વિનિમય બાજાર મેં રૂપાય એક પેસે મજબૂત હોકર 83.96 પ્રતિ ડાલર પર ખુલા। શુરૂઆતી સૌંદર્યોનું કે બાદ 83.95 પર

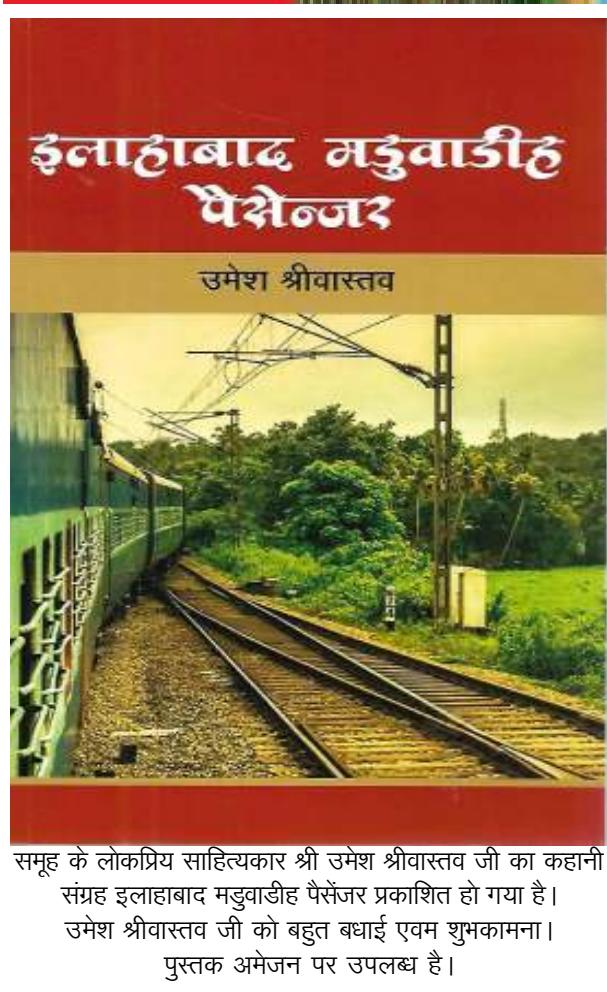
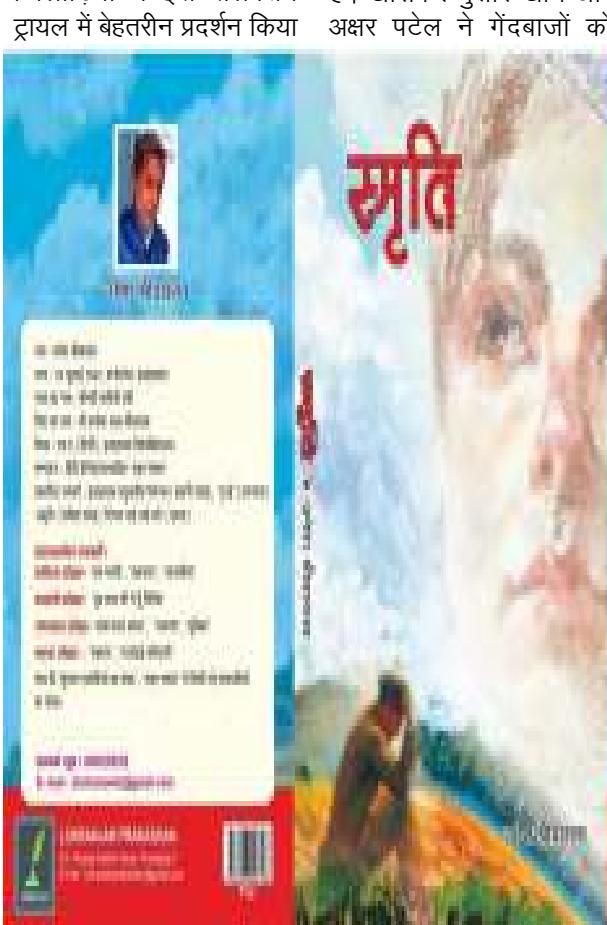


પહુંચ ગયા ગયા જો પિછે બંદ સે દો પેસે કી બઢત દર્શાતી હૈ। રૂપાય બૃહસ્પતિવાર કો અમેરિકી ડાલર કે મુકાબલે 83.97 પ્રતિ ડાલર પર બંદ હુંઠા થા। ઇસ બીચ, છે પ્રમુખ મુદ્રાઓનું કે મુકાબલે અમેરિકી ડાલર કે મજબૂતી કો પરખણે વાતા ડાલર સૂચાની 0.10 પ્રતિશત કી ગિરાવટ કે સાથ 97.97 અંક પર રહા। વૈશ્વિક તેલ માનક બ્રેંટ ક્રુડ વાયારા 0.01 પ્રતિશત કી બઢત કે સાથ 72.70 અમેરિકી ડાલર પ્રતિ બેરલ પર કારોબાર કર રહા થા। શેયર બાજારોનું આંકડોનું મુશ્ટાબિક વિદેશી સંસ્થાગત નિવેશક (એફાઈઆઈ) પૂંજી બાજાર મેં બૃહસ્પતિવાર કે બિકાવાલ રહે થે ઔર ઉન્હોને શુદ્ધ રૂપ સે 688.69 કરોડ રૂપયે કી કીમત કે શેયર બેચે।

સેબી ચીફ માધ્યમી પૂરી બુચ હર તરફ સે ધિરી, લગાતાર લગ રહે ગંભીર આરોપ,

અબ જાંચ કી હો રહી તૈયારી

બાજાર નિયામક સેબી ચીફ માધ્યમી પૂરી બુચ લગાતાર આરોપોને સે ધિરી જા રહી હૈ। હિન્ડનબર્ગ કે આરોપોને કે બાદ ઉન્ન પર લગાતાર હમળે હો રહે હૈ। સેબી પ્રમુખ અપને ઊપર લગ રહે સ્થી આરોપોનો નિરાધાર બતા રહી હૈ। ઇસી બીચ સેબી કે પ્રમુખ માધ્યમી પૂરી બુચ કે ખિલાફ કઈ આરોપ લગ ચુકે હૈ, જિન્ની અબ જાંચ કરવાઈ જાએ। ઇસ મહીને કે અંત તક માધ્યમી પૂરી બુચ કે સમિતિ તલબ ભી કર સકતી હૈ। બતા દેં કે માધ્યમી પૂરી બુચ પર ટોકિસ્ક વર્ક કલ્વર સે લેકર આઈસીઆઈ બેંક્સે સે સેલરી લેને કે આરોપ લગ રહે હૈ। ઇન આરોપોને કે બીચ કાગેસ પાર્ટી માધ્યમી પૂરી બુચ સે ઇસ્ટીફા માગ ચુકી હૈ। ઇસી બીચ નિઝ જાનકારી મિલી હૈ કે લોક લેખા સમિતિ ને ઇસ વર્ષ સેબી કે પ્રદર્શન કી સમીક્ષા કરને કો ફેસલા લિયા હૈ। યે જાનકારી ઇકોનોમિક્સ ટાઇમ્સ્સ કે રિપોર્ટ મેં દી ગઈ હૈ। ઇસ સમીક્ષા પ્રક્રિયા કે બુચ કે સંસ્થા તલબ કર સકતી હૈ। એસે મેં માધ્યમી પૂરી બુચ કે સમસ્યા અધિક બઢ સકતી હૈ। ઇસ રિપોર્ટ કી માને તો સિપોર્ટ મેં કહા ગય હૈ કે 29 અગસ્ત કે પૈનલ કી પહલી બેંક મેં કઈ સદર્યોનું દારા જાંચ કી માંગ કિયા ગયા। પોએસી કી અધ્યક્ષતા કે એન્ડોર્સેન્સ ને જો વેલે કો કારણ વો લગાતાર ધિરી દુર્ઘાસ હુંઠે હૈ। એસે સંસ્થાની પર કો કારણ વો લગાતાર ધિરી દુર્ઘાસ હુંઠે હૈ।



સંજ્ઞાન કે આધાર પર જોડા ગયા થા, ક્યાંકી કઈ સદર્યોનું દારા જાંચ કી માંગ કે હો રહે હૈ। એસે સંસ્થાની પર કો કારણ વો લગાતાર ધિરી દુર્ઘાસ હુંઠે હૈ।

સંજ્ઞાન કે આધાર પર જોડા ગયા થા, ક્યાંકી કઈ સદર્યોનું દારા જાંચ કી માંગ કે હો રહે હૈ। એસે સંસ્થાની પર કો કારણ વો લગાતાર ધિરી દુર્ઘાસ હુંઠે હૈ।

સંજ્ઞાન કે આધાર પર જોડા ગયા થા, ક્યાંકી કઈ સદર્યોનું દારા જાંચ કી માંગ કે હો રહે હૈ। એસે સંસ્થાની પર કો કારણ વો લગાતાર ધિરી દુર્ઘાસ હુંઠે હૈ।

સંજ્ઞાન કે આધાર પર જોડા ગયા થા, ક્યાંકી કઈ સદર્યોનું દારા જાંચ કી માંગ કે હો રહે હૈ। એસે સંસ્થાની પર કો કારણ વો લગાતાર ધિરી દુર્ઘાસ હુંઠે હૈ।

સંજ્ઞાન કે આધાર પર જોડા ગયા થા, ક્યાંકી કઈ સદર્યોનું દારા જાંચ કી માંગ કે હો રહે હૈ। એસે સંસ્થાની પર કો કારણ વો લગાતાર ધિરી દુર્ઘાસ હુંઠે હૈ।

સંજ્ઞાન કે આધાર પર જોડા ગયા થા, ક્યાંકી કઈ સદર્યોનું દારા જાંચ કી માંગ કે હો રહે હૈ। એસે સંસ્થાની પર કો કારણ વો લગાતાર ધિરી દુર્ઘાસ હુંઠે હૈ।

સંજ્ઞાન કે આધાર પર જોડા ગયા થા, ક્યાંકી કઈ સદર્યોનું દારા જાંચ કી માંગ કે હો રહે હૈ। એસે સંસ્થાની પર કો કારણ વો લગ

संक्षिप्त

शहबाज शरीफ सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने भृष्टाचार रोधी कानून के बदलावों को दी मंजूरी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ सरकार को बड़ी राहत देते हुए भृष्टाचार रोधी कानून में हुए बदलावों को लागू करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज इसा ने संघीय सरकार और अन्य पक्षों द्वारा दायर इंट्रा-कोर्ट अपील पर यह फैसला दिया है। पांच जजों की पीठ ने बीती 6 जून को इस मामले में अपना फैसला सुनिश्चित रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जायबदेही व्यूरो (छ छ) कानूनों में संशोधन को पूर्व में रद्द कर दिया था,



लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया है। मई 2023 में शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान सरकार ने भृष्टाचार रोधी राष्ट्रीय जायबदेही व्यूरो कानूनों में संशोधन किया था। इसमान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीकी-ए-इंसाफ पार्टी ने इस कानून की आलोचना की थी और दावा किया था कि इसके कारण आपील अली जरदारी, शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ जैसे प्रमुख राजनेताओं के खिलाफ भृष्टाचार के मामले वापस ले लिए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री खान ने संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने पिछले साल सितंबर में बदलावों को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ पाकिस्तान की संघीय सरकार ने किसे को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रास्क फौर्स गठित करेंगे। उन्होंने ही उन्होंने यह तक कह दिया कि इसका नेतृत्व टेस्ला के सीईओ एलन मस्क करेंगे।

क्या है ट्रास्क फौर्स का मकसद?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि ट्रास्क फौर्स का उद्देश्य पूरी संघीय सरकार का विचारणा और

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया है। मई 2023 में शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान सरकार ने भृष्टाचार रोधी राष्ट्रीय जायबदेही व्यूरो कानूनों में संशोधन किया था। इसमान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीकी-ए-इंसाफ पार्टी ने इस कानून की आलोचना की थी और दावा किया था कि इसके कारण आपील अली जरदारी, शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ जैसे प्रमुख राजनेताओं के खिलाफ भृष्टाचार के मामले वापस ले लिए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री खान ने संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने पिछले साल सितंबर में बदलावों को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ पाकिस्तान की संघीय सरकार ने किसे को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रास्क फौर्स का उद्देश्य पूरी संघीय सरकार का विचारणा और

रूस ने अमेरिका को यूक्रेन मुद्दे पर 'हृद' पार न करने की चेतावनी दी

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह यूक्रेन के मुद्दे पर रेड लाइन को पार न करे। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टीएसएस (तास) द्वारा जारी की गई खबर में यह जानकारी दी गई। खबर में बताया गया कि लावरोव ने बुधवार को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने के मामले में लक्षण रेखा (रेड लाइन) पार कर दी है। खबर में लावरोव के हावाले से कहा गया, "उह्ने (अमेरिका को) यह समझ लेना चाहिए कि हमारी लक्षण रेखा ऐसी नहीं हैं जिनसे खिलाफ किया जा सके और वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे कहाँ हैं।" लावरोव ने कहा कि अमेरिका रूस के प्रति आपसी संयम की भावना खोने लगा है। उन्होंने इसे 'खतरनाक' कहा दिया।

'हिस्परेट': अमेरिका ने साजिश के लिए लूसियों के खिलाफ अभियोग का दायरा बढ़ाया

अमेरिकी न्याय विभाग ने तथाकथित 'हिस्परेट' मैलवेयर हमले के जरिए यूक्रेन और अमेरिका सहित नाटो के 26 सहयोगियों के कंप्यूटर प्रणाली को नष्ट करने के लिए लूसियों के खिलाफ लगाए गए अभियोग में अन्यांशों की शामिल किया है। अमेरिकी सरकार ने प्रतिवादियों की गिरफ्तारी में मदद करने वाले लोगों को छह करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम देने की घोषणा की है।



अप्रीन तिमोविच स्टिगल का नाम था। एक संघीय अधिकारी ने कहा कि जनवरी 2022 में हुए 'हिस्परेट' मैलवेयर हमले के यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का पहला प्रयास था। जो बाइडन के लिए एक संघीय कर आरोपों को स्वीकार कर आश्वर्यजनक कदम उठाया। जो बाइडन के लिए नें लॉस एंजिलिस में संघीय अदालत में जूरी का चयन शुरू होने के कुछ घंटों बाद यह आश्वर्यजनक कदम उठाया। न्याय विभाग द्वारा किये गए इस मुकदमे में हंटर बाइडन पर कम से कम 14 लाख अमेरिकी डॉलर का कर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है। हंटर बाइडन को बंदूक संबंधी मामले में जून में दोषी ठहराया गया था और उन्हें इस मामले में कुछ ही महीनों में सजा सुनाए जाने की संभावना है। न्यायाधीश ने कर मामले से जुड़े नी आरोपों को पढ़ा जिसके तुरंत बाद हंटर बाइडन ने कहा, "मैं दोषी हूं।" इन आरोपों के तहत 17 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन सजा संघीय दिशा-निर्देशों में बहुत कम सजा का प्रावधान है। इस मामले में सजा 16 दिसंबर को सुनाई जाएगी।

अमेरिका: हंटर बाइडन ने संघीय कर आरोपों को स्वीकार किया

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन ने अपैथेट रूप से बंदूक खेलने के मामले में दोषी करार कर दिए एक और आपारिक अपीलों की सुनवाई से बचने के लिए एक संघीय कर आरोपों को स्वीकार कर आश्वर्यजनक कदम उठाया। जो बाइडन के लिए नें लॉस एंजिलिस में संघीय अदालत में जूरी का चयन शुरू होने के कुछ घंटों बाद यह आश्वर्यजनक कदम उठाया। न्याय विभाग द्वारा किये गए इस मुकदमे में हंटर बाइडन पर कम से कम 14 लाख अमेरिकी डॉलर का कर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है। हंटर बाइडन को बंदूक संबंधी मामले में जून में दोषी ठहराया गया था और उन्हें इस मामले में कुछ ही महीनों में सजा सुनाए जाने की संभावना है। न्यायाधीश ने कर मामले से जुड़े नी आरोपों को पढ़ा जिसके तुरंत बाद हंटर बाइडन ने कहा, "मैं दोषी हूं।" इन आरोपों के तहत 17 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन सजा संघीय दिशा-निर्देशों में बहुत कम सजा का प्रावधान है। इस मामले में सजा 16 दिसंबर को सुनाई जाएगी।

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा वादा- चुनाव जीतने के बाद बनाएंगे टास्क फौर्स

वॉशिंगटन। अमेरिका में पांच नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में, रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हॉर्स मैदान में हो गए हैं। वहीं, मस्क ने रिपब्लिकन उम्मीदवार के फैसले का खीच पूर्व राष्ट्रपति हॉर्स ने दोषीय चुनाव किया है। उन्होंने कहा कि ट्रास्क फौर्स गठित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।

पुराने नियमों करेंगे खत्म ट्रंप ने गुरुवार को कहा, शक्ति कीमतों पर इसे रोकने के लिए मैं आज प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि मेरे दूसरे कायाकाल में हम कम दस पुराने नियमों को खत्म कर देंगे। हर किसी के लिए नए विधायक बनाए जाएं।

ट्रंप का खत्म करने के लिए एक अपील कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रास्क फौर्स गठित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने यह तक कह दिया कि इसका नेतृत्व टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सीधे गठित करेंगे।

क्या है ट्रास्क फौर्स का मकसद?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि ट्रास्क फौर्स बनाने की बहुत जरूरत है।

उन्होंने आगे कहा, शेल्टर एलन मस्क ने मुझे अपना पूरा समर्थन दिया है। वह एक समझदार



जिसमें अमेरिका को क्रिप्टो और बिटकॉइन के लिए विश्व राजधानी बनाना शामिल है। ट्रास्क फौर्स बनाने की बहुत जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रास्क फौर्स गठित करने के साथ एक सरकारी दक्षता आयोग (ग्रामेट इंफीशिएर्स कमिशन टास्क) बनाऊंगा। हमें इसे बनाने की बहुत जरूरत है। इसे उस तरह से नहीं बनाया जाएगा। और अनुचित भुगतान धोखाधड़ी और अनुचित भुगतान को पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक कायाकाल का विश्वास होगा।

उनकी सलाह पर ही फैसला लिया है। वह जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सराहना की बहुत जरूरत है। इसे उस तरह से नहीं बनाया जाएगा। और अगले दिन एक अपील करने के लिए एक सरकारी दक्षता आयोग बनाए जाएगा।

उनकी सलाह पर ही फैसला लिया है। वह जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सराहना की बहुत जरूरत है। इसे उस तरह से नहीं बनाया जाएगा। और अगले दिन एक अपील करने के लिए एक सरकारी दक्षता आयोग बनाए जाएगा।

उनकी सलाह पर ही फैसला लिया है। वह जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सराहना की बहुत जरूरत है। इसे उस तरह से नहीं बनाया जाएगा। और अगले दिन एक अपील करने के लिए एक सरकारी दक्षता आयोग बनाए जाएगा।

उनकी सलाह पर ही फैसला लिया है। वह जानते हैं कि वह क्या कर रहे